

भारत में बेरोजगारी : एक अध्ययन

डा० विभा कुमारी

शिक्षिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेन्द्र नगर, पटना-800016 (बिहार)

भारत में आज गरीबी और असमानता प्रचुर मात्रा में मौजूद है। 115 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ बेरोजगार और 32 करोड़ लोग अति गरीब है। भारत में आज भी विकास के फायदे बड़ी आबादी तक नहीं पहुँच पाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 1990 के पहले की अपेक्षा आज गरीबी उन्मूलन के लिए तीन गुणा ज्यादा विकास दर की आवश्यकता है। 1990 के दौरान गरीब ओर अमीर के बीच जो अंतर 30 अंक था वह बढ़कर 51 अंक हो गया है। भारत में 1999-2000 में अति गरीबों की संख्या 26 करोड़ थी। 2004-05 में यह संख्या बढ़कर 30 करोड़ दर्ज की गई और 2011-12 में यह 36 करोड़ हो गयी।

अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। आज जो आर्थिक असमानताएं भारत में मौजूद है उनका पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव पड़ा पड़ा है। एक गरीब व्यक्ति को घटिया प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होता है जबकि दूसरी तरफ ऐसे सम्पन्न लोग भी हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हैं। आज देश में कुल 205 हजार करोड़पति हैं। देश का सारा विकास ओर सारी योजनायें केवल 205 हजार इन लोगों को ही अधिक लाभ पहुँचा रही है। वर्ष 2006-07 में कुल बजट प्राप्ति का 40 प्रतिशत धन इन 205 हजार लोगों को कर छूट में दे दिया गया। इन्हें सस्ती जमीन, सस्ता बैंक ऋण, कर छूट, सब्सिडी, सस्ती बिजली सब कुछ मुहैया कराया जाता है। भारत की यही दर्दनाक सच्ची तस्वीर है।

हमारे देश में लघु उद्योग बंद होते जा रहे हैं। कृषि उत्पादन दिन-प्रति-दिन कम होता जा रहा है। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इस कारण यहाँ बेरोजगारी का स्वरूप औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों की अपेक्षा भिन्न है। भारत जैसे विकासशील देश में बेरोजगारी का समाधान करने के लिए पूंजी-वस्तुओं के स्टॉक को बढ़ाना अनिवार्य है ताकि उत्पादन की नयी इकाइयाँ कायम की जाएँ। इससे अतिरिक्त रोजगार क अवसरों का सृजन करके अतिरिक्त जनसंख्या को लाभपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। रोजगार जनन का मुख्य स्रोत असंगठित क्षेत्र है, जिसमें स्वरोजगार और लघु व्यापार शामिल है और इसके द्वारा अर्थव्यवस्था के कुल

रोजगार में 92 प्रतिशत योगदान किया जाता है। इसकी मुख्य रोजगार जनन क्रियायें निम्नलिखित हैं:-

- कृषि एवं संबंधित कार्य।
- व्यापार, रेस्तरां एवं होटल (पर्यटन सहित)
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य
- लघु एवं मध्यम उद्योग

लघु और मध्यम उद्योगों द्वारा कुल विनिर्माण रोजगार का 80 प्रतिशत जुटाया गया और इसकी सापेक्ष रोजगार लोच संगठित क्षेत्र के 3.8 गुणा से भी अधिक है। अतः रोजगार पर अनुकूल प्रभाव प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि विनिर्माण क्षेत्र की संरचना का अनुपात लघु एवं मध्यम उद्यमों की ओर परिवर्तित किया जाए। साथ ही कृषि रोजगार का एक मुख्य स्रोत है। यदि इस क्षेत्र के लिए उचित नीति अपनायी जाए तो यह क्षेत्र रोजगार-जनन की दृष्टि से सोने की खान बन सकता है और इसके लिए इस क्षेत्र के विभिन्न अंगों में श्रम-प्रधान एवं उच्च मूल्य वाली क्रियाओं जैसे बागवानी, पुष्प-कृषि तथा छोटी सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा देना होगा।

अब प्रश्न यह उठता है कि विकास का वैकल्पिक मॉडल कौन सा हो जिसमें सकल देशीय उत्पाद की वृद्धि के साथ रोजगार को प्रोत्साहित किया जा सके? विकास के वर्तमान मॉडल की मूल समस्या यह है कि इसमें सकल देशीय उत्पाद को विकास प्रधान सूचक समझा जाता है। अतः आर्थिक समीक्षा में विकास के मापदण्ड के रूप में सकल देशीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति सकल देशीय उत्पाद, निवेश और बचत, निर्यात और आयात, थोक कीमत सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आदि आते हैं परंतु अभी तक इनके रोजगार या इसकी गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभावों का सटीक अध्ययन नहीं किया गया है। अतः उन मुख्य क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जो रोजगार-वृद्धि में योगदान देते हैं। 2011-12 में रोजगार में मुख्य योगदान देने वाले क्षेत्र हैं:- कृषि (52 प्रतिशत), विनिर्माण (13 प्रतिशत), व्यापार (8 प्रतिशत) और अन्य सेवायें (11 प्रतिशत)। ये चार क्षेत्र मिलकर कुल रोजगार का 84 प्रतिशत जुटाते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि विनिर्माण क्षेत्र में 86 प्रतिशत रोजगार लघु उद्योगों द्वारा जुटाया जाता है। बड़ी एवं मध्यम इकाइयों का इसमें योगदान केवल 24 प्रतिशत ही है।

यदि रोजगार-उपलब्धता का सकल देशीय वृद्धि दर से तालमेल बिठाना है तो कृषि-विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा जैसे कृषि के क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्रों में अभी रोजगार के विस्तार की काफी सम्भावनायें हैं। सिंचाई का विस्तार और वाटरशेड डेभलपमेन्ट कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और इसके साथ-साथ रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सुधार उपरान्त काल में, कृषि विकास कार्यक्रमों में काफी मन्द गति अनुभव की गई। सिंचाई मूल तत्व है जिसकी सहायता से अधिक उपजाऊ बीजों के कार्यक्रम का विस्तार होता है साथ ही ऊर्वरकों के उपयोग में भी वृद्धि होती है। इसके साथ ही व्यर्थ भूमि के विकास में पंचायतों का सहयोग लाभदायक हो सकता है। इससे रोजगार-सृजन में सहायता मिलेगी।

विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार-वृद्धि में मुख्य अंशदाता लघु-स्तर तथा अनौपचारिक क्षेत्र है जिसे प्रायः असंगठित क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। हाल की सरकारी नीतियों ने लघु-स्तर के उपयोग क्षेत्र को भारी नुकसान पहुँचाया है। इससे रोजगार वृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लघु क्षेत्र की इकाइयों की मुख्य समस्या उधार का है। यदि सरकार इन्हें दिए जाने वाले

उधार की राशि बढ़ा दे, तो इससे रोजगार का विस्तार करने में बहुत अधिक लाभ हो सकता है। गृह निर्माण क्षेत्र भी एक श्रम प्रधान कार्य है और यदि राज्य अपने लक्ष्य "सभी के लिए मकान" को पूरा करना चाहता है, तो इससे भी व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन होगा। सड़कों का विस्तार, गाँवों को शहरी केन्द्रों के साथ जोड़ने, कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलने और चार लेन वाले राजमार्गों के रूप में आधार संरचना कायम करने के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार से अधिक रोजगार सृजन के साथ ही व्यापार को लढ़ावा मिलेगा।

सूचना तकनीक आज देश में शिक्षित युवाओं के लिए अनेक रोजगार के अवसर सृजित कर रहा है। एक अनुमान के अनुसार सूचना तकनीक के विभिन्न सम्भागों में आज भारत के 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त सूचना तकनीक क्षेत्र 22 लाख कम्प्यूटर व्यवसायियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराता है।

तालिका-1

राज्य स्तरीय युवा बेरोजगारी दरें (2011-2012) प्रति 1000 व्यक्ति (15-29 वर्ष)

क्र० सं०	राज्य	ग्रामीण	शहरी
1.	केरल	300	250
2.	तमिलनाडु	150	140
3.	असम	130	200
4.	आंध्र प्रदेश	99	48
5.	उड़ीसा	100	200
6.	बिहार	90	190
7.	महाराष्ट्र	104	165
8.	हरियाणा	81	83
9.	गुजरात	58	85
10.	कर्नाटक	58	105
11.	मध्य प्रदेश	40	130
12.	उत्तर प्रदेश	61	125
13.	पंजाब	70	95
14.	राजस्थान	44	88
15.	हिमाचल प्रदेश	61	205
	अखिल भारतीय	90	154

स्रोत:- योजना आयोग, 2011

इस दृष्टि से सूचना तकनीक क्षेत्र का रोजगार अवसरों के विस्तार की दृष्टि से उज्ज्वल भविष्य है। इसलिए सरकार को कम्प्यूटर शिक्षा गाँवों और देश के दूरदराज के इलाकों में पहुँचाने के लिए मुख्य भूमिका अदा करनी होगी। आज उदारीकरण के कारण बार-बार श्रमिकों को संगठित होने

से असंगठित क्षेत्र की ओर धकेला जा रहा है। इस प्रक्रिया को पलटना होगा।

उपरोक्त परिस्थिति में सरकार को सुधारों की पुनः समीक्षा करनी चाहिए और सुधार प्रक्रिया का इस प्रकार संशोधन करना चाहिए ताकि बेरोजगारी की समाप्ति और

“काम के अधिकार” को एक बुनियादी हक के तौर पर स्वीकार करने को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए विकास का एक नया मॉडल तैयार करना होगा। इसके साथ ही अनौपचारिक क्षेत्र को उन्नत करने की आवश्यकता है। नगर

आयोजन की अवधारणा में ऐसा परिवर्तन करना होगा कि इससे अनौपचारिक क्षेत्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही इसके विकास में आने वाली कठिनाईयों को दूर किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची:—

1. रीता माथुर, भारतीय अर्थव्यवस्था, विनायक बुक्स, पटना।
2. बी0एल0 माथुर, श्रम प्रबंध, विनायक बुक्स, पटना।
3. राजीव कुमार, आर्थिक नियोजन, विनायक बुक्स, पटना।
4. डी0 कुमारी, विकास का अर्थशास्त्र, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
5. एम0एल0 मोर्य, श्रम अर्थशास्त्र, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
6. रेणु त्रिपाठी, ग्रामीण विकास और निर्धमता उन्नमूलन, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
7. अग्रवाल बबीता, श्रम अर्थशास्त्र, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
8. शर्मा ए0के0, मजदूरी नीति तथा सामाजिक सुरक्षा, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
9. कुमार अनिल, भारत में विकास की चुनौतियाँ, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।